यातायात में बाधक अवैध धार्मिक स्थलों की सूची प्रस्तुत करें : हाईकोर्ट

- सोमवार को विभिन्न याचिकाओं पर हुई सुनवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. सोमवार को हाईकोर्ट में यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अपने-अपने तर्क और सवाल किए. खास बात यह रही कि हाईकोर्ट ने यातायात में बाधक अवैध धार्मिक स्थलों की सूची प्रशासन को प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

शहर के यातयात को लेकर आज जस्टिस विनय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच में सुनवाई थी. सुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल और डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी उपस्थित हुए. नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने डबल बेंच को बताया कि बीआरटीएस पूरा तोड़ दिया है और सभी 17 बाद स्टॉप हटा दिए गए हैं. इसके बाद यातायात अव्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने कोर्ट को अवगत कराया कि रोबोट चौराहे से रेडिसन चौराहे तक दिनभर यातायात जाम रहता है. वहां के सर्विस रोड ठीक नहीं है. इसी तरह शहर के अनेक मुख्य मार्गो और सर्विस रोड खुदे होने से यातायात जाम लगा रहता है. बागड़िया ने कोर्ट को बताया कि पीक समय में शहर में भी लोग यातायात जाम से परेशान हैं. दो पहिया वाहन चालकों पर नियंत्रण नहीं है, वे सिंगल तोड़कर इधर-उधर से कहीं भी घुस जाते है, जिससे दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है. जस्टिस शुक्ला और अवस्थी ने डीसीपी यातायात को हाई कोर्ट के यातायात प्रबंधन समिति के साथ समन्वय करके समस्त का स्थाई समाधान करने के निर्देश दिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने शहर के मुख्य सड़कों और अन्य सड़कों पर यातायात में बाधक अवैध धार्मिक स्थलों की सूची अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने के आदेश दिए. उक्त मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी.

वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा के पूछे नियम

हाईकोर्ट में यातायात व्यवस्था को लेकर सुनवाई में जस्टिस विनय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी ने डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी से पूछा कि वीवीआईपी और वीआईपी के लिए यातायात के क्या नियम है. डीसीपी ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है. सुरक्षा की दृष्टि से यातायात रोका जाता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए. उक्त बात पर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने सवाल उठाया कि वीवीआईपी और वीआईपी निकलने के बाद यातायात पुलिस और जवान गायब हो जाते है और चौराहे लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद यातायात जाम हो जाता है.

यातायात में स्टॉफ के कमी-झेलावत: वरिष्ठ अधिवक्ता विनय झेलावत ने सुनवाई के दौरान बताया कि इंदौर में स्वीकृत यातायात कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में 237 यातायात कर्मी कम है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और संबंधित विभाग यातायात बल की पूर्ति करे.

चौराहे पर कोने में खड़े होकर सिपाही चालान बनाते रहते हैं: बागड़िया: यातायात व्यवस्था को लेकर जारी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आज वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट के पुराने निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. चौराहों पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी मौजूद नहीं रहते हैं. यदि रहते है तो कोने में खड़े होकर चालान बनाते हुए देखा जा सकता है. शहर में 24 सिग्नल चालू नहीं है अभी भी. बागडिया ने सुनवाई के दौरान डीसीपी को कोर्ट में कहा कि मेरे साथ कार में बैठकर चलिए, पुलिस कर्मी नजर आते है या नहीं. इस बार दोनों न्यायाधीश ने कहा कि सड़कों और चौराहों पर यातायात पुलिस के जवान नहीं दिखते हैं.

प्रशासन ने दो स्थानों पर सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण

- प्रशासन द्वारा खजराना और गाडराखेड़ी में कार्रवाई
- 30 करोड़ की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त, 12 मकान हटाए

नव भारत न्यूज

इंदौर. सोमवार को शहर में प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर करोड़ों की सरकारी जमीन मुक्त कार्रवाई. शहर के जूनी इंदौर और मल्हारगंज तहसील में अतिक्रमण हटाकर 35 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन खाली कराई गई. खास बात यह है कि एक जमीन सरकार ने लोक परिसंपत्ति व्ययन के तहत बेच जा चुकी है.

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है. इस क्रम में आज प्रशासन ने कार्रवाई कर खजराना में 30 करोड़ रुपए मूल्य की बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया. एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने बताया कि सरकारी सीलिंग की जमीन खसरा क्रमांक 442/1 की 30,000 वर्गफीट पर अतिक्रमण कर पक्के मकानों का निर्माण कर लिया गया था. आज उक्त 12 मकानों को हटाने की कार्रवाई की गई. इसी तरह एसडीएम मल्हारगंज निधि वर्मा ने ग्राम गाडराखेडी में 3 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए 9 मकानों में से आज 7 मकान तोड़ने की कार्रवाई की. बचे दो मकानों पर हाईकोर्ट का स्टे होने से कार्रवाई नहीं की जा सकी है. प्रशासन ने उक्त गाडराखेड़ी की 14 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन को लोक परिसंपत्ति व्ययन नियम के तहत हेमर स्मिथ इंटरप्राइजेस को 22- 23 में बेचा दिया था. मौके पर 3 हजार फीट जमीन पर 9 मकान बने हुए थे. कार्रवाई के दौरान एसीपी खजराना कुंदन मंडलोई, तहसीलदार राकेश सस्तिया, अपर तहसीलदार कमलेश कुशवाह,अशोक परमार, थाना प्रभारी मनोज सेंधव, रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे तथा राजस्व, पुलिस और नगर निगम का रिमूवल अमले के कर्मचारी मौजूद थे.

नगर निगम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश दरकिनार

- आज अवमानना याचिका पर पेशी

नव भारत न्यूज

इंदौर. नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट ने विनियमित कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने के आदेश दिए थे. निगम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर सिर्फ 10 वीं और 12 वीं पास कर्मचारियों को ही पक्का किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि 10 और 12 वीं पास को स्थाई किया जाए. उक्त मामले को लेकर आज श्रम न्यायलय में अवमानना याचिका की पेशी है. नगर निगम विनियमित कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए थे कि समान काम समान वेतन के पात्र है विनियमित कर्मचारी भी. कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से सभी 2001 तक के विनियमित कर्मचारी को समान काम समान वेतन के हिसाब से 1391 कर्मचारी को पक्का करना था. वर्तमान में 1391 कर्मचारी में से 970 कर्मचारी ही बचे हैं, इनमें कुछ की मृत्यु और अन्य कारणों से नौकरी से बाहर हो चुके हैं. निगम कमिश्नर ने 7 लोगों की टीम बनाई थी और उन्हें समय सीमा में सभी कर्मचारी को पक्का करना था, लेकिन निगम के ही कुछ लोगों द्वारा निगम कमिश्नर को भ्रमित कर दिया गया. आयुक्त को झूठी और गलत जानकारी देकर जो 10 वीं और 12 वीं पास हैं, उन्हें ही पक्का करने की तैयारी हो चुकी है, जिसमें 488 कर्मचारी है. बाकी 482 कर्मचारी को शामिल नहीं किया गया है. उक्त 482 कर्मचारियों को स्थापना विभाग एवं लेखा विभाग में भेजी गई सूची में शामिल नहीं किया गया है. उक्त मामले को लेकर अधिवक्ता ओमप्रकाश लटके द्वारा एसएलपी और अवमानना याचिका दायर की गई है. आज श्रम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवेहलना और कर्मचारियों के साथ भेदभाव लगने पर सुनवाई है.

15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों पर कार्रवाई की तेज

इंदौर. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर द्वारा स्टेज कैरिज परमिट पर संचालित पुरानी यात्री बसों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

वर्ष 2025 में 2010 और उससे पुराने मॉडल की बसों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 136 वाहन स्वामियों ने तय समय में अपनी बसों का प्रतिस्थापन नहीं किया, जिसके चलते उनके स्थायी परमिट रद्द कर दिए गए. उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार वाहन की आयु की गणना पंजीयन तिथि से की जाती है. इसी आधार पर 2 जनवरी 2026 को 2011 मॉडल की 136 बसों के मालिकों को नई बसों से प्रतिस्थापन करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 64 मालिकों ने अपनी बसें बदल ली हैं, जबकि 72 बस मालिकों ने अब तक ऐसा नहीं किया है.

इन 72 बसों की सूची पुलिस, जिला परिवहन अधिकारियों और परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड को भेज दी गई है, ताकि यदि ये बसें संचालित पाई जाती हैं तो उन्हें जप्त किया जा सके।इन बसों के परमिट निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी जारी है.

एक नजर में

भीम पेमेंट्स ऐप पर अब सिबिल स्कोर उपलब्ध

इंदौर. क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल ने आज एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी भुगतान ऐप भीम पेमेंट्स ऐप में उपभोक्ता सिबिल स्कोर और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट के एकीकरण की घोषणा की. इस एकीकरण के माध्यम से भीम ऐप के उपयोगकर्ता ऐप के भीतर ही अपने सिबिल स्कोर और महत्वपूर्ण क्रेडिट जानकारी को सुरक्षित रूप से एक्सेस, देख और ट्रैक कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी क्रेडिट स्थिति की बेहतर समझ मिलेगी. इस साझेदारी पर ट्रांसयूनियन सिबिल के एमडी और सीईओ भावेश जैन ने कहा मजबूत और सुदृढ़ क्रेडिट इकोसिस्टम के केंद्र में क्रेडिट जागरूकता और क्रेडिट समावेशन होते हैं. भीम पेमेंट्स ऐप अपने करोड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए सिबिल स्कोर और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को आसानी से सुलभ बनाएगा. एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड की एमडी और सीईओ, ललिता नटराज ने कहा ट्रांसयूनियन सिबिल के साथ हमारे सहयोग के माध्यम से, हम इस दृष्टिकोण को क्रेडिट जागरूकता तक विस्तारित कर रहे हैं, जिससे उपयोगकर्ता भीम ऐप के भीतर आसानी से अपना सिबिल स्कोर एक्सेस कर सकें.

एयू बैंक ने 'एयू रॉयल बैंकिंग प्रोग्राम' की शुरुआत की

इंदौर. अपने 31वें फाउंडेशन डे के अवसर पर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए एयू रॉयल बैंकिंग प्रोग्राम के शुभारंभ की घोषणा की. यह एक संरचित, सुरक्षित और प्रोफेशन-सेंट्रिक प्रीमियम बैंकिंग इकोसिस्टम है, जिसे विशेष रूप से भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस और अनुपालन के संरक्षकों कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है. लॉन्च पर उत्तम त्रिवेदी, डिप्टी सीईओ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कंपनी सेक्रेटरीज़ कॉरपोरेट भारत में संस्थागत विश्वास, गवर्नेंस की शुचिता और नियामकीय अनुशासन को बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं. आईसीएसआई के साथ हमारी विशेष साझेदारी के बाद, एयू रॉयल बैंकिंग प्रोग्राम सीएस प्रोफेशनल्स को उनकी पेशेवर ज़िम्मेदारियों और विकसित होती आवश्यकताओं के अनुरूप एक सुरक्षित, पारदर्शी और रिलेशनशिप-आधारित बैंकिंग इकोसिस्टम प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. पवन जी. चांडक, अध्यक्ष आईसीएसआई ने कहा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ यह सहयोग कंपनी सेक्रेटरीज़ को उनके महत्वपूर्ण पेशेवर योगदान और विकसित होती आवश्यकताओं के समर्थन हेतु प्रोफेशन-अलाइन बैंकिंग समाधानों से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

सेमसंग की विरासत सिर्फ उत्पादों तक सीमित नहीं

इंदौर. भारत में सेमसंग की कहानी का एक पहलू वह है जिसे लोग अक्सर मार्केट शेयर, स्मार्टफोन लॉन्च और नोएडा की उस विशाल फैक्ट्री से जोड़ते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माण इकाइयों में से एक है. यह कहानी निश्चित रूप से प्रभावशाली है, लेकिन पूरी तस्वीर पेश नहीं करती. यह कहानी भारत के मानव संसाधन के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. यह कहानी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के स्कूलों में, महाराष्ट्र की कोडिंग लैब्स में और आईआईटी दिल्ली के इनक्यूबेशन सेंटर में लिखी जा रही है. सेमसंग साउथवेस्ट एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट एसपी चुन कहते हैं, भारत में तीन दशक पूरे करते हुए, हम मानते हैं कि इनोवेशन और शिक्षा प्रगति का आधार भी हैं और सभी को साथ लेकर चलने का माध्यम भी. आगे हमारा फोकस इस बात पर है कि इस क्षमता को बड़े स्तर पर असरदार बनाया जाए. सेमसंग में हम ऐसे युवा इनोवेटर्स को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनमें कौशल, रचनात्मकता और मिलकर काम करने की सोच हो, ताकि वे जटिल सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकें और एक बेहतर व समावेशी भविष्य बना सकें.

इंटेलिस्मार्ट की मध्य प्रदेश में भी एंट्री

इंदौर. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से एक बड़ा ऑर्डर मिला है. कंपनी इंदौर और उज्जैन क्षेत्रों में लगभग 5 .57 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी। इस जीत के साथ ही इंटेलिस्मार्ट ने मध्य प्रदेश में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है. इस नए प्रोजेक्ट के साथ कंपनी का पैन-इंडिया ऑर्डर बुक अब 2 .28 करोड़ स्मार्ट मीटर तक पहुंच गया है, जो उद्योग क्षेत्र में सबसे बड़ा ऑर्डर बुक में से एक है. इस बारे में इंटेलीस्मार्ट के एमडी एवं सीईओ अनिल रावल ने कहा कि नए राज्यों में हमारा बढ़ता कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र के डिजिटलीकरण में नेतृत्व करने और ग्रामीण स्तर पर सार्थक बदलाव लाने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटरिंग सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि डिस्कॉम्स को सशक्त बनाने, उपभोक्ता अनुभव को बेहतर बनाने और देश के लिए एक मजबूत, लचीले ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का माध्यम है. हम विश्वास करते हैं कि यह प्रोजेक्ट रिवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) ढांचे के तहत मध्य प्रदेश की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा को तेज करेगा.

डेली कॉलेज के मामले में दिग्विजय सिंह ने ली आपत्ति

- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण

इंदौर. प्रदेश और देश के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज परिसर का बार-बार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उनसे जुड़े संगठनों के कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने पर संस्थान की निष्पक्षता, गरिमा एवं स्वतंत्र पहचान को गंभीर क्षति पहुँची है. उक्त बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं डेली कॉलेज, इंदौर के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने कही है. उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि डेली कॉलेज एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था है, जिसकी 140 वर्षों से अधिक की गौरवशाली परंपरा रही है. ऐसी संस्था को किसी भी प्रकार के राजनीतिक या वैचारिक कार्यक्रमों का मंच बनाना पूरी तरह अनुचित है. दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि हाल ही में कई अवसरों पर कॉलेज परिसर संस्थान को एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक चिंताजनक पैटर्न का रूप ले चुकी हैं. उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम डेली कॉलेज परिसर में आयोजित नहीं किया गया था. दिग्विजय ने कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मांग की है कि वे तत्काल स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति दी गई? क्या स्वीकृतियां प्रदान की गईं, तथा क्या इस संबंध में कोई नीति मौजूद है. साथ ही, उन्होंने यह भी पूछा है कि हाल के वर्षों में ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मांग की है कि तत्काल एक स्पष्ट नीति जारी करें, जिसमें कॉलेज परिसर को किसी भी राजनीतिक या वैचारिक कार्यक्रम उपयोग करने पर प्रतिबंध हो.

विपक्ष की एकजुटता ने विफल की साजिश : रीना

- कांग्रेस शुरू से महिला सशक्तिकरण की पक्षधर

नव भारत न्यूज

इंदौर. संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका. इससे साफ हो गया है कि देश अब विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा. मोदी सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के माध्यम से सत्ता पर एकाधिकार जमाने की जो साज़िश रची थी, इंडिया गठबंधन (विपक्ष) की एकजुटता ने उसे विफल कर दिया है.

यह बात पत्रकारों से प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया ने कही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही है. राहुल गांधी के नेतृत्व में यह मांग लगातार उठाई जाती रही है कि महिलाओं को उनका अधिकार बिना किसी शर्त और देरी के मिलना चाहिए. लेकिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं से जोड़कर इसे लागू करने में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं के साथ एक सुनियोजित राजनीतिक छल करने का प्रयास किया गया है, जिसे विपक्ष की एकजुटता ने संसद में विफल कर दिया. संसद में कुल 528 मतों में से विधेयक के पक्ष में केवल 298 वोट, जबकि विरोध में 230 मत पड़े, इसके फलस्वरूप यह असंवैधानिक संशोधन गिर गया है. कांग्रेस आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संसद में मिली जीत का स्वागत करती है.

ओबीसी महिलाओं की भागीदारी तय हो

उन्होंने कहा कि बिना जातिगत जनगणना के परिसीमन कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के अधिकार प्रभावित होंगे. कांग्रेस मांग करती है कि सरकार अपनी मंशा साफ करे और वर्तमान 543 लोकसभा सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण निर्धारित करे. आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी महिलाओं की भागीदारी तय होनी चाहिए, जिसे भाजपा लगातार दरकिनार कर रही है. चर्चा में प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया, हिमानी सिंह, पार्षद सोनिला मीमरोट, शशि हाड़ा सहित महिला कांग्रेस की पदाधिकारी मौजूद थी.

छह महीने बाद भी 90 डिग्री एंगल ब्रिज की डिजाइन पर निर्णय नहीं

- मामला पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन एमआर 4 ब्रिज का

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन एमआर-4 लक्ष्मी बाई नगर रेलवे ओवर ब्रिज की डिजाइन तय नहीं की जा रही है. इस बात को 7 माह से ज्यादा समय बीत चुका हैं. शहर में ब्रिज के अधूरे निर्माण से हजारों लोग परेशान हो रहे है. यातायात जाम की स्थिति भी बनी रहती है. खास बात यह है कि उक्त ब्रिज 90 डिग्री एंगल का बनाया जा रहा था और उसका खुलासा नव भारत ने किया था.

इंदौर में पीडब्ल्यूडी द्वारा शहर के एमआर 4 पर लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का ओवर ब्रिज निर्माण कार्य लंबे समय से बंद है. उक्त ब्रिज 90 डिग्री एंगल से निर्माण होने का मामला सामने आने के बाद से काम बंद पड़ा है. उक्त ब्रिज निर्माण को लेकर अभी तक पीडब्ल्यूडी कुछ तय नहीं कर पा रहा है और ब्रिज की डिजाइन भी नई नहीं आई है. उक्त 90 डिग्री ब्रिज निर्माण का खुलासा नव भारत द्वारा करने के बाद पीडब्ल्यूडी ने ब्रिज का निर्माण कर रोक दिया था. मौके पर जाकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और वरिष्ठ इंजीनियरों ने खबर की पुष्टि की थी. इसके बाद कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने और ब्रिज के डिजाइन बदलने का निर्णय किया गया था. सात महीने बीत चुके है, लेकिन मुख्य अभियंता कार्यालय भोपाल द्वारा ब्रिज की डिजाइन तय नहीं के जा सकी है. नवभारत ने 25 जून 2025 को एमआर 4 पर लक्ष्मीबाई नगर और 4 जुलाई 2025 को 90 डिग्री ब्रिज निर्माण की खबर छापी थी. उसमें बताया गया था कि कहां तक ब्रिज के पीलर खड़े हो गए और सिंहस्थ फंड से बनी सड़क पर बिना सोचे समझे पीलर खड़े कर दिए है.

काम अधूरा पड़ा, लोग हो रहे परेशान

ब्रिज का निर्माण रियाल कंस्ट्रक्शन कर रही है. फिलहाल ब्रिज का काम अधूरा पड़ा है और ब्रिज डिजाइन का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है. इस कारण भागीरथपुरा और लक्ष्मीबाई नगर आने जाने वाले लाखों औधोगिक कर्मचारियों और रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बारे में एसडीओ मनोज जैन ने कहा कि भोपाल से ब्रिज की डिजाइन बदलने और नई डिजाइन पास होकर नहीं आई है. इसी कारण काम बंद पड़ा है.

गोशाला का निर्माण कार्य शुरू

इंदौर. स्वामी परमानंद गौशाला विकास समिति द्वारा- अक्षय तृतीया पर निर्माण कार्य शुरू किया गया. विकास समिति के अध्यक्ष रामबाबू अग्रवाल और पूरी टीम द्वारा जय गोपाल, जय गौशाला के नारे के साथ गोपूजन कर एक जुलूस निकालकर निर्माण स्थल पर पहुंचकर, पूजा-अर्चना के साथ निर्माण कार्य शुरू किया गया. इस अवसर पर साध्वी आदित्याजी, संरक्षक किशनलाल पाहवा, अध्यक्ष- रामबाबू अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मांगीलाल कासट, समाजसेवी हरि एवं अशोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष- रुशि भाई, संगठन राजेश अग्रवाल, विष्णु कटारिया, विजय शादीजा, श्रीमती गुप्ता आदि मौजूद थे. इस अवसर पर कई दानदाताओं ने गौशाला हेतु राशि भेंट की.

अक्षय तृतीया पर ग्राहकों ने डीपी ज्वेलर्स से समृद्धि का किया स्वागत

इंदौर. अक्षय तृतीया खरीदी के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस शुभ मुहुर्त पर जो लोग आभूषण खरीदने का सोच रहे थे, उनके लिए डी.पी.ज्वेलर्स सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन साबित हुआ क्योंकि यहां वेडिंग सीजन के अनुरुप आकर्षक कलेक्शन संजोया गया था. इस बार का सबसे खास आकर्षण 50000 से भी अधिक डिज़ाइनर, वेडिंग, नेचुरल डाइमंड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल, एंटीक, पोल्की ज्वेलरी का लेटेस्ट कलेक्शन रहा. जो कस्टमर्स वेडिंग सीज़न हेतु गहने खरीदना चाहते थे उनके लिए यह शानदार सौगात साबित हुआ. यहाँ पर सोने व चाँदी के सिक्कों की विशाल रेंज उपलब्ध थी.

इस शुभ अवसर पर ग्राहकों को अक्षय तृतीया का अधिक लाभ पहुंचाने के लिए शोरूम सुबह 10.30 बजे से ही खुले हुए थे. ग्राहकों में आभूषणों की खरीदी को लेकर काफी उत्साह देखा गया. उनका कहना था कि यहां आभूषण पूर्णत: शुद्ध एवं सही मेकिंग चार्जेस के साथ बिना किसी नियम एवं शर्तों के ख़रीदे जा सकते हैं इसलिए आभूषणों की खरीदी के लिए डी.पी.ज्वेलर्स उनकी पहली पसंद है. डी.पी.ज्वेलर्स के अनिल कटारिया ने बताया, मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर आभूषण खरीदी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इस अटूट परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ग्राहक बड़ी संख्या में आभूषण व सिक्कों की खरीदी करते हैं. हमने ग्राहकों के समक्ष खास आधुनिक पैटर्न के साथ ही पारंपरिक व डिजाइनर आभूषण पेश किए. डीपी ज्वेलर्स हमेशा से ग्राहकों की पसंद और उनके फायदे को प्राथमिकता देता आया है। डीपी ज्वेलर्स की गोल्ड ज्वेलरी बीआईएस हॉलमार्क युक्त व डायमंड ज्वेलरी आईजीआई सर्टिफाइड होती है. डीपी ज्वेलर्स ने सम्पूर्ण उत्तर व मध्य भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है. अपने अति सुंदर डिजाइनों और बिज़नेस में सम्पूर्ण पारदर्शिता की वजह से आज डी.पी. ज्वेलर्स सभी का पसंदीदा ब्रांड बन गया है.

एक नजर में

विश्व धरोहर दिवस पर विशेष आयोजन,

हेरिटेज लोको बना आकर्षण का केंद्र

नवभारत न्यूज़

इंदौर. पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर इंदौर एवं रतलाम रेलवे स्टेशनों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए. इंदौर रेलवे स्टेशन पर भी इस अवसर पर विशेष गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें स्टेशन परिसर में स्थित हेरिटेज स्टीम लोको की साफ-सफाई कर उसे संरक्षित रखने का संदेश दिया गया.

इसी क्रम में रतलाम रेलवे स्टेशन पर स्थित हेरिटेज स्टीम लोको को आकर्षक रूप से सजाया गया, जो वहां मौजूद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. कार्यक्रम के तहत रतलाम स्टेशन पर प्रभावशाली फॉगिंग एवं साउंड शो का आयोजन किया गया,

जिसके माध्यम से दर्शकों को भारतीय रेलवे की समृद्ध विरासत से अवगत कराया गया. रेलवे अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य हेरिटेज लोको के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करना और रेलवे कर्मचारियों व यात्रियों में धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था. इस अवसर पर मंडल यांत्रिक अभियंता सहित यांत्रिक विभाग के पर्यवेक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में यात्री उपस्थित रहे.